Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अगस्त (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- मास हिस्टीरिया 3
- चीन सीमा से सटी दो सड़कों के निर्माण को मिली हरी झंडी 3
- उत्तराखंड शुरू करेगा 'किसान प्रोत्साहन योजना' 4
- उत्तराखंड से आम, शहद, राजमा का पहली बार निर्यात 4
- उत्तराखंड में 1202 मोबाइल टावरों को मंज़ूरी 5
- ज्योतिर्लिंग सर्किट से जुड़ेंगे देश के 12 ज्योतिर्लिंग 5
- उत्तराखंड की 12 महिलाओं-किशोरियों को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार 6
- वनस्पति वैज्ञानिकों ने विकसित की नीम की छह प्रजातियाँ 7
- उत्तराखंड में 108 की तर्ज़ पर पहली बार पशुओं के लिये शुरू होंगी एंबुलेंस 7
- उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु लागू होगी नई पर्यटन नीति 8
- उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाएगी कर्मकार बोर्ड 9
- गंगाजल को अमृत बनाने वाले मित्र जीवाणु हो रहे विलुप्त 9
- देवीधुरा में फल और फूलों से खेली गई रोमांच से भरी बग्वाल 10
- मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा 10
- 13 वीर नारियों और 12 सैन्य अधिकारियों को वीरता पुरस्कार 11
- सोनप्रयाग-केदारनाथ तक बनेगा उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे 11
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना 12
- केंद्र ने ऋषिकेश के विकास का प्रस्ताव जर्मन बैंक को भेजा 12
- उत्तराखंड में गठित होगा उत्पादों के लिये जीआई बोर्ड 13
- उत्तराखंड के सात ज़िलों में खुलेंगे क्रिटिकल केयर सेंटर 13
- उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड के बेहतर संचालन हेतु बनेगा 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट' 14
- देहरादून-अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ 14
- मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 15
- राज्य में 33 नए पर्यटन स्थलों पर बनेंगे हेलीपैड और हेलीपोर्ट 15
- 5 जी नेटवर्क के लिये पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड 16

नोट :

उत्तराखंड

मास हिस्टीरिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के एक स्कूल से कुछ बच्चों के बिना किसी वजह एकसाथ रोने, चीखने, ज़मीन पर लोटने, सिर पटकने और रोते-रोते बेहोश हो जाने की घटना हुई, जिसे 'मास हिस्टीरिया'का मामला माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- सूत्रों के अनुसार यह घटना उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के रैखोली जूनियर हाईस्कूल की है, जिसमें रोती-चीखती, बेसुध होती लड़कियाँ 8वीं कक्षा की बताई जा रही हैं। कुल 8 बच्चों में ये दिक्कत पाई गई थी। इनमें 6 छात्राएँ और 2 छात्र थे।
- बागेश्वर के डिप्टी सीएमओ हरीश पोखरियाल ने बताया कि बच्चों से बात करके पता चला कि वे पहले से घबराए हुए थे और खाली पेट स्कूल आए थे। उन्होंने कहा कि यह मामला मास हिस्टीरिया का है या नहीं? यह पूरी जाँच के बाद ही साफ होगा। हालाँकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड में इस तरह के 'मास हिस्टीरिया'के मामले पहले भी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली ज़िलों के स्कूलों में देखे गए हैं।
- 'मास हिस्टीरिया ' के सभी उदाहरणों में लोगों के अचानक चीखने, रोने और बेहोश होने की घटनाएँ दर्ज की गई हैं। साल 2018 में नेपाल के प्यूथान ज़िले के स्कूल में एक 9 साल की बच्ची रोने और चीखने लगी थी, देखते-ही-देखते स्कूल में 47 बच्चों को रोते और चीखते हुए पाया गया था। उसी स्कूल में साल 2017 और साल 2016 में भी एक ही दिन कई बच्चों में एक जैसे बर्ताव या लक्षण देखे गए थे। इसे रिपीट होने वाले 'मास हिस्टीरिया ' का अनूठा मामला माना गया था।
- इसके अलावा, मई 2001 में भारत की राजधानी दिल्ली में मंकीमैन की अफवाह ने भी मास हिस्टीरिया का रूप ले लिया था। लोगों ने सूरज ढलने के बाद घर से निकलना बंद कर दिया था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन पर मंकीमैन ने हमला किया। तीन लोगों की मौत हो गई थी, जो डर से भागने के दौरान छत से गिर गए थे। लोगों के शरीर पर नाखून और दाँतों के निशान मिले थे। पूरे मामले की जाँच के बाद पुलिस ने मंकीमैन को महज़ एक अफवाह बताया था। बाद के अध्ययनों से साफ हुआ कि यह 'मास हिस्टीरिया' था।
- हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'मास हिस्टीरिया'के मामलों में ज़्यादातर देखा-देखी और सुनी-सुनाई बातों के ज़रिये कोई घटना होती देखी गई है। जैसे दूसरों में जो बर्ताव, हरकत या लक्षण लोग देखते या सुनते हैं, अक्सर खुद भी वही करने लगते हैं या महसूस करते हैं।
- कोई खतरा जो असल में न हो, लेकिन उस खतरे के प्रति लोगों के एक समूह में डर हो, ऐसी स्थिति के लिये भी कुछ एक्सपर्ट्स 'मास हिस्टीरिया'शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
- 'मास हिस्टीरिया'के पीछे कोई अफवाह, हरकत, सोच, डर या खतरा जैसी चीज़ें होती हैं। इसके लक्षण वास्तविक होते हैं, भले ही उसके पीछे असल में कोई खतरा या स्वास्थ्य समस्या न हो। मास हिस्टीरिया के लक्षण अचानक शुरू और खत्म हो जाते हैं। इसके लक्षणों में सीने में दर्द, सुस्ती, सिर दर्द, बेहोशी, कांपना, आंशिक पैरालिसिस, हँसने या रोने लगना शामिल हैं। जाँच-पड़ताल के बाद भी इसमें दिखने वाले लक्षणों या हरकतों की वजह का पता नहीं चलता।

चीन सीमा से सटी दो सड़कों के निर्माण को मिली हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे उत्तरकाशी ज़िले की दो सीमांत सड़कों के निर्माण के लिये वन भूमि हस्तांतरण को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने अनुमति दे दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुई बैठक में 28 किमी. लंबी इन दोनों सड़कों के लिये सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को 62.05 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। अब जल्द ही सामरिक महत्त्व की इन सड़कों का निर्माणकार्य प्रारंभ हो सकेगा।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिये रोपवे के प्रस्ताव भी रखे गए थे। इन दोनों रोपवे से संबंधित प्रस्तावों में कुछ जानकारियाँ अपूर्ण थीं। इसे देखते हुए इन पर चर्चा नहीं हो पाई और बोर्ड ने इन्हें अगली बैठक के लिये टाल दिया।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की वर्ष 2020 में हुई बैठक में उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत पड़ने वाली दो सड़कों-सुमला से थांगला (11 किमी.) व मंडी से सांगचोकला (17 किमी.) के लिये क्रमश: 30.29 हेक्टेयर व 31.26 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इसे अनुमोदन के लिये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा गया था।

उत्तराखंड शुरू करेगा 'किसान प्रोत्साहन योजना'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार की 'किसान सम्मान निधि योजना' की तर्ज पर उत्तराखंड में 'किसान प्रोत्साहन योजना (केपीवाई)' शुरू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। हालाँकि मुख्यमंत्री ने केपीवाई का पूरा विवरण नहीं दिया, उन्होंने कहा कि सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक किसानों की आय को दोगुना करना है।
- गौरतलब है कि 24 फरवरी, 2019 से लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों, जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि हो, को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6 हज़ार रुपए (तीन महीने में 2,000 रुपए) की राशि प्रदान की जाती है।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 108 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम पैक्स) के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया और मवेशियों के लिये कुल मिक्स राशन (टीएमआर) तैयार करने के लिये चारबा इकाई शुरू की।
- इस अवसर पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग की ओर से 13 लाख सदस्यों के डाटा के संग्रहण व डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया की गई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड 108 एमपीएसीएस को ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने 41 लाख हितग्राहियों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3700 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। सहकारी बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) घटी हैं और वे अब लाभ में आ गई हैं।
- उन्होंने कहा कि महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री घास्यारी कल्याण योजना (एमजीकेवाई)' का तीन लाख से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया है। एमजीकेवाई को 15 अगस्त से राज्य के सभी पर्वतीय ज़िलों में विस्तारित किया जाएगा।

उत्तराखंड से आम, शहद, राजमा का पहली बार निर्यात

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एपिडा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहली बार निर्यात के लिये भेजे जा रहे स्थानीय आम, शहद और राजमा से लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से राज्य में उत्पादित 5 टन आम, 28 टन राजमा और 80 टन शहद की खेप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिये भेजी गई।
- राज्य से प्रथम बार राज्य के कास्तकारों द्वारा उत्पादित आम की चौंसा एवं लंगड़ा प्रजातियों के उच्च गुणवत्तायुक्त फलों का निर्यात दुबई को किया जा रहा है।
- किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शहद का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को किया जा रहा है। राजमा के निर्यात को बढ़ावा देते हुए राज्य के कृषकों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त राजमा का निर्यात भी संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जा रहा है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गुणात्मक वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि उत्पादकों को अच्छा बाज़ार उपलब्ध कराने के लिये उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- धामी ने कहा कि राज्य में किसानों की आजीविका बढ़ाने एवं सभी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिये कृषि कैलेंडर भी बनाया गया है। राज्य में जल्द किसान प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी।

उत्तराखंड में 1202 मोबाइल टावरों को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिये 1202 बीएसएनएल के मोबाइल टावर को मंज़ूरी दी है। केंद्र सरकार एक मोबाइल टावर पर एक करोड़ रुपए खर्च करेगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 6 अगस्त को नई दिल्ली के दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक शिष्टाचार भेंट में केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति प्रदान की।
- मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उन सभी स्थानों की सूची सौंपी है, जहाँ मोबाइल टावर लगाए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से इन इलाकों के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
- मोबाइल टावर लगाए जाने से सबसे ज़्यादा फायदा सीमांत ज़िले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी को होगा। इन ज़िलों के अलावा राज्य के अन्य पर्वतीय ज़िलों और मैदानी ज़िलों के ग्रामीण इलाकों में भी कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो सकेगी।
- प्रस्ताव के अनुसार अल्मोड़ा में 28, बागेश्वर में 97, चमोली में 123, चंपावत में 103, देहरादून में 56, पौड़ी में 196, हरिद्वार में 06, नैनीताल में 60, पिथौरागढ़ में 245, रुद्रप्रयाग में 20, टिहरी में 114, यूएस नगर में 05, उत्तरकाशी में 149 मोबाइल टावर लगेंगे

ज्योतिर्लिंग सर्किट से जुड़ेंगे देश के 12 ज्योतिर्लिंग

चर्चा में क्यों ?

6 अगस्त, 2022 को हरिद्वार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में ज्योतिर्लिंग सर्किट बनाने की तैयारी की जा रही है। इस सर्किट के माध्यम से देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री ने बताया कि कम अवधि में चार्टर प्लेन से देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ज्योतिर्लिंग सर्किट के माध्यम से श्रद्धालु कर सकेंगे। इसके लिये जिन जगहों पर एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर उन एयरपोर्ट का लाभ लिया जाएगा। वहीं कई जगहों पर हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाएगा।

नोट :

- पर्यटन मंत्री ने बताया कि ज्योतिर्लिंग सर्किट के साथ ही प्रदेश में नाथ संप्रदाय सर्किट बनाकर उसे गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। इसके लिये उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश सरकार जल्द ही एमओयू साइन करेगी।
- पर्यटन मंत्री ने कहा कि पहाड़ों में नाथ संप्रदाय का बहुत प्रचार रहा है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की बहुत गुफाएँ हैं। नाथ सर्किट बनाकर गोरखपुर के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाएगा।
- जिन प्रदेशों में ज्योतिर्लिंग हैं, उन प्रदेशों से भी ज्योतिर्लिंग सर्किट बनाने की बात शुरू हो गई है। यह सर्किट केदारनाथ से शुरू होगा और जहाँ-जहाँ पर ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ से जोड़ा जाएगा।

उत्तराखंड की 12 महिलाओं-किशोरियों को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने राज्य की 12 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया, साथ ही 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता सम्मान दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को वीरबाला तीलू रौतेली के नाम पर प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है।
- गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिये तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरूआत की थी।
- इसके तहत राज्य सरकार 31 हज़ार रुपए व प्रशस्ति पत्र देती है। पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार राशि 31 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपए किये जाने की घोषणा की थी, लेकिन इस बार भी पुरस्कार राशि 31 हज़ार ही प्रदान की गई है।
- हाल ही में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश में बदलाव कर पुरस्कारों की अधिकतम संख्या तय की गई है। प्रदेश में अब हर साल अधिकतम 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार मिलेगा। हर ज़िले से एक महिला को इसके लिये चयनित किया जाएगा। वहीं 35 आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा।
- विभिन्न क्षेत्रों में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित महिलाएँ एवं किशोरियाँ-
  - साहित्यिक क्षेत्र - डॉ. शशि जोशी (ज़िला- अल्मोड़ा),
  - खेल - दीपा आर्य (ज़िला- बागेश्वर), प्रेमा नौटियाल (ज़िला- ऊधमसिंहनगर), प्रियंका प्रजापति (ज़िला- हरिद्वार),
  - सामाजिक क्षेत्र - मीना तिवारी (ज़िला- चमोली), लता नौटियाल (ज़िला- उत्तरकाशी)
  - बालिका शिक्षा एवं सामाजिक कार्य - मंजू बाला (ज़िला-चंपावत),
  - पत्रकारिता - नलिनी गोसाई (ज़िला- देहरादून),
  - शिक्षा एवं स्वच्छता - विद्या मर्तोलिया (ज़िला- नैनीताल),
  - अदम्य साहसिक कार्य - सावित्री देवी (ज़िला- पौड़ी),
  - महिला स्वयं सहायता - दुर्गा खड़ायत (ज़िला- पिथौरागढ़),
  - आजीविका संवर्द्धन - गीता रावत (ज़िला- रुद्रप्रयाग),
- आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पुरस्कार से सम्मानित महिलाएँ हैं- सुनीता कोहली, कुसुम बिष्ट, जानकी व कमला नेगी (ज़िला- अल्मोड़ा), हेमा सती (ज़िला- बागेश्वर), भागा देवी, शोभा व अभिलाषा देवी (ज़िला- चमोली), अनिता रावत (ज़िला- चंपावत), अर्चना राणा, सरोज सुयाल व किर्तना शर्मा (ज़िला- देहरादून), सीमा रानी, कमलेश धीमान, रचना व उमेश कुमारी (ज़िला- हरिद्वार), ज्योति रावत, अंजू सागर व गीता नयाल (ज़िला- नैनीताल), अनिता देवी, आशा देवी,मीना देवी, हेमलता बिष्ट व गिन्नी डंगवाल, (ज़िला- पौड़ी), दीपा पांडेय व ज्योति टम्टा (ज़िला- पिथौरागढ़), रंजना अवस्थी (ज़िला- रुद्रप्रयाग), मंगला थपलियाल, उमा भट्ट व सविता सेमवाल, (ज़िला- टिहरी), स्नेहलता मलिक, रचना रानी व मीरा देवी (ज़िला- ऊधमसिंह नगर) सुमित्रा और लक्ष्मी नौटियाल (ज़िला- उत्तरकाशी)।

नोट :

वनस्पति वैज्ञानिकों ने विकसित की नीम की छह प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को वन अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञानी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि वनस्पति विज्ञानियों ने नीम की छह नई प्रजातियाँ विकसित की हैं। इससे उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में नीम का अधिक-से-अधिक उत्पादन करने के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत किया जा सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में निबौली और नीम के तेल की भारी मांग को देखते हुए नीम की छह नई प्रजातियाँ विकसित की गई हैं। नई प्रजातियाँ सामान्य की तुलना में कई गुना बेहतर हैं। विकसित की गईं नई प्रजातियों से निबौली और तेल का अधिक उत्पादन होगा।
- नई प्रजातियों से नीम के सामान्य पौधे की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक तेल का उत्पादन होगा। परिणामस्वरूप तेल की मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।
- संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक नई प्रजातियाँ सामान्य नीम की तुलना में तीन साल पहले ही फल देना शुरू कर देंगी। सामान्य नीम के पौधे छह साल में निबौली का उत्पादन करते हैं। सामान्य नीम के पौधे से निकलने वाली एक किलोग्राम निबौली से जितना तेल का उत्पादन होगा, उतना ही तेल नई प्रजातियों की नीम से मात्र 300 ग्राम बीज से किया जा सकेगा।
- सभी प्रजातियों में अजादरेक्टिन तत्त्व की मात्रा सामान्य की तुलना में बहुत अधिक पाई गई है। सामान्य नीम के बीजों में जहाँ अजादरेक्टिन की मात्रा 1000 पीपीएम है, वहीं नई प्रजातियों में इसकी मात्रा दस हज़ार पीपीएम पाई गई है।
- संस्थान के वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार मौजूदा समय में देश में सिर्फ 35 लाख टन निबौली और सात लाख टन तेल का उत्पादन हो रहा है, जो मांग के अनुरूप बहुत कम है।
- देश में यूरिया के उत्पादन में नीम के तेल की मांग के साथ ही एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, एंटी वायरल और एंटीबैक्टीरियल दवाइयों को बनाने के साथ ही नीम के तेल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक वस्तुओं को बनाने में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
- नीम की प्रजाति भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में पाई जाती है तथा अब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका महाद्वीप तक पहुँच गई है।
- भारत समेत पूरी दुनिया में नीम के बीजों और तेल की भारी मांग को देखते हुए चीन जैसे देशों में कई करोड़ हेक्टेयर में नीम की खेती की जा रही है। अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ चीन जैसे देशों में नीम को लेकर बड़े पैमाने पर शोध भी किये जा रहे हैं।
- नीम एक ऐसा वृक्ष है, जिसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। नीम के वृक्ष को वेदों में सर्वरोग निवारिणी के रूप में उल्लेखित किया गया है। वेदों में इसे दैव वृक्ष माना गया है।

उत्तराखंड में 108 की तर्ज़ पर पहली बार पशुओं के लिये शुरू होंगी एंबुलेंस

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश में इंसानों के लिये संचालित 108 एंबुलेंस की तर्ज़ पर पहली बार पशुओं के इलाज हेतु पशु चिकित्सा एंबुलेंस शुरू की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश सरकार पशुपालन व्यवसाय में रोज़गार के नए अवसर सृजित करने तथा पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिये पहली बार पशुपालकों को घर पर भी बीमार पशुओं के इलाज की सुविधा देने जा रही है।
- इसके लिये पहले चरण में 60 पशु चिकित्सा एंबुलेंस खरीदने हेतु सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने से किसानों को घर पर ही बीमार पशु का इलाज कराने के लिये एंबुलेंस सेवा मिलेगी।

नोट :

- राज्य में खेती-किसानी और पशुपालन लोगों की आजीविका का मुख्य साधन हैं। 8.5 लाख किसान परिवार पशुपालन से जुड़े हैं, जिनकी बड़े पशु (गाय व भैंस) का पालन से आजीविका चलती है। प्रदेश में लगभग 27 लाख बड़े पशु हैं। इसके अलावा दो लाख परिवार छोटे पशु (भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, खच्चर) का व्यवसाय कर रहे हैं।
- प्रदेश में अभी तक बीमार पशु का घर-द्वार पर इलाज कराने की सुविधा नहीं है। किसानों को बीमार पशु को उपचार के लिये पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र में ले जाना पड़ता है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुर्गम क्षेत्रों में बीमार पशुओं को समय पर इलाज न मिलने के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
- गौरतलब है कि पशुओं के इलाज के लिये वर्तमान में 323 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। इसके अलावा 770 पशु सेवा केंद्र, 682 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, चार पशु प्रजनन फार्म हैं। दुर्गम क्षेत्रों में बीमार पशुओं को समय पर इलाज न मिलने के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु लागू होगी नई पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये सरकार जल्द ही नई नीति लागू करेगी। इसके लिये विभाग की ओर से नई पर्यटन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटन विकास परिषद से पारित कर जल्द ही नीति को अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिये कैबिनेट में रखा जाएगा। इस नीति में निवेशकों को सरकार एमएसएमई से अधिक निवेश प्रोत्साहन राशि देगी। इससे आने वाले समय में प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
- नई नीति में उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति की तर्ज़ पर उत्तराखंड में भी निवेशकों को ज्यादा प्रोत्साहन देने का प्रावधान होगा। जिससे फाइव स्टार होटल, रेस्टोरेंट, साहसिक पर्यटन के लिये अवस्थापना विकास में सरकार की ओर से निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अभी तक एमएसएमई उद्योगों की तर्ज़ पर सरकार पर्यटन उद्योगों को एक से डेढ़ करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि दे रही है, जबकि अन्य राज्यों में पर्यटन उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलने से निवेशक उत्तराखंड में कम रुचि दिखा रहे हैं। जिससे सरकार ने नई नीति में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर निवेशकों को आकर्षित करने जा रही है।
- नई पर्यटन नीति में निवेश प्रोत्साहन राशि को डेढ़ करोड़ से बढ़ा कर दो करोड़ किया जा सकता है। इसके अलावा इंटर सब्सिडी को 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, एसजीएसटी में पाँच साल तक की छूट, स्थानीय वास्तुकला के आधार पर भवन निर्माण करने पर अतिरिक्त अनुदान राशि का प्रावधान किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र में महिला उद्यमियों को अलग से प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। इसके बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग आदि साहसिक पर्यटन में निवेश करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- होटल व्यवसाय में सीवरेज सिस्टम, सौर ऊर्जा के लिये निवेशकों को अतिरिक्त राहत देने का प्रावधान किया जाएगा।
- राज्य सरकार को पर्यटन क्षेत्र में 1116 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, इसमें लगभग 5122 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे लगभग 19 हज़ार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- सरकार का मानना है कि नई नीति के बनने से राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश में तेजी आएगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही सेवा क्षेत्र से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 2019 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर पर्यटन नीति लागू की गयी थी। जिसमें पर्यटन उद्योगों को भी एमएसएमई, मेगा इंडस्ट्रियल नीति के तहत प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई थी।
- विनिर्माण उद्योग की तर्ज पर ही पर्यटन उद्योगों को 10 से 200 करोड़ रुपए का निवेश करने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत या अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए, मैदानी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ रुपए की छूट, बिजली बिलों में एक रुपए प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति और विद्युत ड्यूटी में पाँच साल की छूट दी जाती है।

नोट :

उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाएगी कर्मकार बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के श्रम सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का दोबारा गठन की तैयारी कर रही है। जल्द ही इसका गठन हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- श्रम सचिव ने बताया कि कर्मकार बोर्ड भंग होने की वजह से श्रमिकों के लिये नई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू नहीं हो पा रही हैं। चूँकि, इन पर निर्णय बोर्ड ही लेता है, इसलिये सरकार दोबारा बोर्ड के गठन की तैयारी कर रही है।
- बोर्ड में वर्तमान में पुरानी योजनाओं का लाभ तो श्रमिकों को मिल रहा है लेकिन उनके कल्याण की कोई नई योजना नहीं बन पा रही है। दोबारा बोर्ड बनने के बाद करीब साढ़े चार लाख श्रमिकों को नई सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी।
- गौरतलब है कि प्रदेश में वर्ष 2017 में श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देख रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर शासन ने अक्टूबर 2020 में हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाकर शमशेर सिंह सत्याल की अध्यक्षता में नया बोर्ड बनाया था।
- वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 सितंबर, 2021 को बोर्ड को दोबारा भंग करते हुए सत्याल को हटा दिया था। तब से श्रम सचिव को पदेन अध्यक्ष बनाते हुए बोर्ड संचालित किया जा रहा है।

गंगाजल को अमृत बनाने वाले मित्र जीवाणु हो रहे विलुप्त

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध से खुलासा हुआ है कि गंगा की सहायक नदियों अलकनंदा और भागीरथी के जल को सेहतमंद बनाने वाले मित्र जीवाणु (माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स) प्रदूषण के कारण तेज़ी से विलुप्त हो रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वीपी उनियाल की देखरेख में डॉ. निखिल सिंह व अन्य ने दोनों नदियों में अलग-अलग स्थानों पर मित्र जीवाणु (माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स) की जाँच की। 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी)' के तहत वैज्ञानिकों ने अलकनंदा नदी में माणा (बदरीनाथ) से लेकर देवप्रयाग तक और भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक अध्ययन किया।
- वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक कई स्थान पर या तो मित्र जीवाणु पूरी तरह गायब हैं या उनकी संख्या बेहद कम है। यही स्थिति अलकनंदा नदी में माणा से लेकर देवप्रयाग तक पाई गई है। दोनों नदियों में माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स का कम पाया जाना इस बात का संकेत है कि यहाँ पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है।
- दोनों नदियों में मित्र जीवाणुओं का अध्ययन ईफेमेरोपटेरा, प्लेकोपटेरा, ट्राइकोपटेरा (ईपीटी) के मानकों पर किया गया। यदि किसी नदी के जल में ईपीटी इंडेक्स बीस फीसदी पाया जाता है तो इससे साबित होता है कि जल की गुणवत्ता ठीक है। यदि ईपीटी इंडेक्स तीस फीसदी से अधिक है तो इसका मतलब जल की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। लेकिन, दोनों नदियों में कई जगहों पर ईपीटी का इंडेक्स 15 फीसदी से भी कम पाया गया है, जो चिंताजनक पहलू है।
- पूर्व में जलविज्ञानियों द्वारा किये गए शोध में यह बात सामने आई है कि गंगाजल में बैट्रियाफोस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो गंगाजल के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थ को खाता रहता है। इससे गंगाजल की शुद्धता बनी रहती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार गंगाजल में गंधक की बहुत अधिक मात्रा पाए जाने से भी इसकी शुद्धता बनी रहती है और गंगाजल लंबे समय तक खराब नहीं होता है।
- वैज्ञानिक शोधों से यह बात भी सामने आई है कि देश की अन्य नदियाँ पंद्रह से लेकर बीस किमी. के बहाव के बाद खुद को साफ कर पाती हैं और नदियों में पाई जाने वाली गंदगी नदियों की तलहटी में जमा हो जाती है, लेकिन गंगा महज़ एक किमी. के बहाव में खुद को साफ कर लेती है।

नोट :

- ऑल वेदर रोड के साथ ही नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर किये जा रहे विकास कार्यों का मलबा सीधे नदियों में डाला जा रहा है। नदियों के किनारे बसे शहरों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार गंगाजल में अन्य नदियों के जल की तुलना में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरी नदियों की तुलना में गंगा में गंदगी को हजम करने की क्षमता 20 गुना अधिक पाई जाती है।
- उल्लेखनीय है कि गंगा नदी में डॉल्फिन समेत मछलियों की 140, सरीसृपों की 35 और स्तनधारी जीवों की 42 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भागीरथी, अलकनंदा, महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, सरयू, यमुना, सोन और महानंदा गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ हैं।

देवीधुरा में फल और फूलों से खेली गई रोमांच से भरी बग्वाल

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में माँ वाराही के धाम देवीधुरा के खोलीखांड दुबाचौड़ मैदान में फल और फूलों से विश्वप्रसिद्ध बग्वाल मेला का आयोजन किया गया। चारखाम (चम्याल, गहड़वाल, लमगड़िया, वालिग) और सात थोक के योद्धा बग्वाल में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- चंपावत ज़िले के प्रसिद्ध देवीधुरा में 'माँ वाराही मंदिर' में रक्षाबंधन के दिन होने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले को 'पत्थर मार' मेला भी कहा जाता है। इस मेले को देखने देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु देवीधुरा पहुँचते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि देवीधुरा में बग्वाल का यह खेल पौराणिक काल से चला आ रहा है। कुछ लोग इसे कत्यूर शासन से चला आ रहा पारंपरिक त्योहार मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे काली कुमाऊँ से जोड़कर देखते हैं।
- प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में चार खामों के लोगों द्वारा अपनी आराध्या वाराही देवी को मनाने के लिये नर बलि देने की प्रथा थी। माँ वाराही को प्रसन्न करने के लिये चारों खामों के लोगों में से हर साल एक नर बलि दी जाती थी। बताया जाता है कि एक साल चमियाल खाम की एक वृद्धा के परिवार की नर बलि की बारी थी। परिवार में वृद्धा और उसका पौत्र ही जीवित थे। महिला ने अपने पौत्र की रक्षा के लिये माँ वाराही की स्तुति की। माँ वाराही ने वृद्धा को दर्शन दिये और मंदिर परिसर में चार खामों के बीच बग्वाल खेलने के निर्देश दिये, तब से बग्वाल की प्रथा शुरू हुई।
- चंपावत जनपद के पाटी ब्लॉक के देवीधुरा में माँ वाराही धाम मंदिर के खोलीखांड दुबाचौड़ में हर साल अषाढ़ी कौथिक (रक्षाबंधन) के दिन बग्वाल मेला होता है। पत्थर से शुरू यह बग्वाल मेला बीते कुछ वर्षों से फल-फूलों से खेला जा रहा है। लाखों लोगों की मौजूदगी में होने वाले बग्वाल मेले में चार खामों (चम्याल, गहरवाल, लमगड़िया और वालिग) के अलावा सात थोकों के योद्धा फर्रों के साथ हिस्सा लेते हैं।
- बग्वाल वाराही मंदिर के प्रांगण खोलीखांड में खेला जाता है। इसे चारों खामों के युवक और बुजुर्ग मिलकर खेलते हैं। लमगड़िया व वालिग खामों के रणबाँकुरे एक तरफ, जबकि दूसरी ओर गहड़वाल और चम्याल खाम के रणबाँकुरे डटे रहते हैं।
- गौरतलब है कि 11 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा 'माँ वाराही बग्वाल मेले' को राजकीय मेला घोषित किया था।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिये मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस उप महानिरीक्षक सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस., उपनिरीक्षक रेखा दानू, कृपाल सिंह एवं मुख्य आरक्षी वेद प्रकाश भट्ट को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया।

नोट :

- भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में यूकेएसएसएससी परीक्षा धांधली की जाँच कर रही एसटीएफ की टीम को भी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह, उप निरीक्षक दिलवर सिंह, नरोत्तम बिष्ट, उमेश कुमार एवं विपिन बहुगुणा को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

13 वीर नारियों और 12 सैन्य अधिकारियों को वीरता पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

13 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने 13 वीर नारियों और 12 पूर्व सैनिक व सैन्य अधिकारियों/वर्तमान सैन्य अधिकारियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और जवानों, छात्रों, बलिदानी सैनिकों के स्वजन व पूर्व सैनिकों से बातचीत की।
- राज्यपाल ने कहा कि वीरांगनाओं का राष्ट्र निर्माण के लिये जो समर्पण है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि ये कार्यक्रम ऐसे स्थान पर हो रहा है, जहाँ से देश को पहला परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा जैसा वीर मिला।
- राज्यपाल ने सब एरिया मुख्यालय के अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि उत्तराखंड सैनिक कल्याण बोर्ड की भाँति वह भी पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और बलिदानियों के स्वजनों की जानकारी एकत्र कर डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश के सैनिकों व वीर नारियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
- वीर नारियों के रूप में सुनीता बिष्ट, शांति देवी, चित्रा देवी, लक्ष्मी तोमर, रामप्यारी, उर्मिला देवी, अंजू देवी, पार्वती देवी, विमला देवी, लता देवी, सुजाता थापा, किरन, अनिता देवी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- पूर्व सैनिक व सैन्य अधिकारीयों मे प्रमोद चंद्र भारद्वाज, मेजर जनरल शमशेर सिंह, कोमोडोर ए के सिन्हा, आनरेरी कैप्टन खुसिंग गुरुंग, दल बहादुर लिंबू, देवी प्रसाद, सूबेदार बाग सिंह और सूबेदार मेजर वीर बहादुर पुन (सम्मान उनके दामाद लाल बहादुर ने ग्रहण किया) को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सोनप्रयाग-केदारनाथ तक बनेगा उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को विनोद रांटा (वन भूमि सलाहकार, कार्यदायी संस्था ट्रेवेस्ट्रा कंपनी सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे) ने बताया कि उत्तराखंड में सबसे लंबे रोपवे सोनप्रयाग-केदारनाथ के निर्माण के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- केदारनाथ के लिये 13 किमी. लंबे रोपवे निर्माण की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) ने एक कंपनी को सौंपी है।
- कार्यदायी संस्था के वन भूमि सलाहकार के साथ प्रशासन और वन विभाग द्वारा रोपवे निर्माण के लिये संयुक्त भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- रोपवे निर्माण के लिये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 11 हेक्टेयर भूमि अधिगृहित की गई है। 22 टॉवर के सहारे बनने वाले रोपवे की डिज़ाइन का लेआउट भी कार्यदायी संस्था ने तैयार कर लिया है।

नोट :

- केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून से अनुमति के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा रोपवे निर्माण के लिये 945 करोड़ रुपए की डीपीआर भेज दी जाएगी। मार्च 2023 से सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे पर चार स्टेशन गौरीकुंड, चीरबासा, लिनचोली और केदारनाथ में बनेंगे। रोपवे से एक समय में दो से ढाई हज़ार यात्री एकतरफा जा सकेंगे। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे से 13 किमी. की दूरी लगभग 30 से 35 मिनट में पूरी हो सकेगी।
- गौरतलब है कि वर्ष 2005 में रामबाड़ा-केदारनाथ रोपवे को मंज़ूरी मिली थी। तब उत्तरांचल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने भूमि सर्वेक्षण सहित अन्य औपचारिकताएँ भी पूरी की थीं। शासन को 70 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव भेजा था। शासन स्तर पर रोपवे निर्माण को पीपीपी मोड में कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन किसी भी कंपनी ने निविदा नहीं डाली।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को रेल विकास निगम के परियोजना प्रबंधक के. ओमप्रकाश मालगुडी ने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण में लगे रेल विकास निगम ने 50 किमी. लंबी सुरंग बनाकर तैयार कर दी है। कुल 125 किमी. लंबे ट्रैक का 105 किमी. हिस्सा सुरंगों के अंदर होगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंधक के. ओमप्रकाश मालगुडी ने बताया कि 125 किमी. लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के नौ पैकेज में 80 प्रवेश द्वार होंगे, जिनमें से लगभग 50 प्रवेश द्वार तैयार हो चुके हैं।
- उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा, जैसे- भूकंप, बाढ़ और आग से निपटने के लिये आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की ओर से साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम स्टडी तैयार की गई है। इसे विदेशों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की ओर से जाँचा गया है।
- भूस्खलन से बचने के लिये पोरल स्टेबलाइज़ेशन किया गया है। सभी बातों को ध्यान में रखकर सुरंगों की डिज़ाइन तैयार की गई है। सभी पैकेज में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। किसी भी प्रकार की आपदा से बचने के लिये सुरंगों को सुरक्षित बनाया जा रहा है।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कुल 17 सुरंगें होंगी। 16 सुरंग एनएटीएम (न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड) और सौड़ (देवप्रयाग) से जनासू तक 70 किमी. लंबी सुरंग का निर्माण टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) से किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर साल 2019 से काम शुरू हुआ था। यह 125 किमी. लंबी परियोजना है, जिसमें 105 किमी. रेललाइन सुरंगों के भीतर होगी। यह परियोजना पूरी तरह से ऋषिकेश से आगे कर्णप्रयाग तक पर्वतीय क्षेत्र में बनाई जा रही है।
- इस रेललाइन के लिये कुल 17 सुरंगों का निर्माण हो रहा है। इनमें जिन सुरंगों की लंबाई 6 किमी. से ज़्यादा है, उनके समानांतर एक निकासी सुरंग भी बनाई जा रही है। इस परियोजना में 7 एडिट टनल बनाई जाएँगी, जिनकी लंबाई 4 किमी. तक होगी।

केंद्र ने ऋषिकेश के विकास का प्रस्ताव जर्मन बैंक को भेजा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने योगनगरी ऋषिकेश की एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के लिये जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू को 1600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जर्मन बैंक करेगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ऋषिकेश शहर के इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट (एकीकृत विकास) को लेकर वित्त मंत्रालय ने जर्मन फंडिंग एजेंसी केएफडब्ल्यू को 160 मिलियन यूरो, यानी करीब 1295 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है।
- इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 200 मिलियन यूरो (करीब 1600 करोड़ रुपए) है। परियोजना के लिये केंद्र सरकार व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 80:20 होगा।

नोट :

- ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना से विश्व में योगनगरी के रूप में विख्यात ऋषिकेश नगर में स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- गौरतलब है कि ऋषिकेश में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की भीड़ की वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके लिये ऋषिकेश में एलिवेटेड रोड बनाई जाएंगी, जिनसे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
- इस परियोजना के पूरा होने पर नागरिक जीवन-शैली व जीवन योग्यता मानकों (अर्बन लाइवेबिलिटी स्टैंडर्ड) में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय लोगों के व्यापारिक व आजीविका स्तर में सुधार होगा। नागरिकों व पर्यटकों को बेहतर पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ मिलेंगी। उनके जीविकोपार्जन की गतिविधियों में इजाफा होगा।

उत्तराखंड में गठित होगा उत्पादों के लिये जीआई बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड जैविक विकास परिषद के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने बताया कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की पहचान और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिये जीआई (भौगोलिक संकेत) बोर्ड के गठन का खाका तैयार कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विनय कुमार ने बताया कि आगामी कैबिनेट बोर्ड की बैठक में इसके गठन को हरी झंडी मिल सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जीआई बोर्ड गठित करने की घोषणा की थी। कृषि विभाग ने बोर्ड बनाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज भी दिया है।
- प्रस्तावित बोर्ड में एक अध्यक्ष के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। बोर्ड का काम स्थानीय उत्पादों को चयनित कर जीआई पंजीकरण करने का रहेगा। जीआई टैग मिलने से नकली उत्पाद बाज़ार में बेचने से बचा जा सकेगा।
- बोर्ड में एक या दो विशेष आमंत्रित सलाहकार व विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। कृषि विभाग व उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड में काम करेंगे। इससे सरकार पर बोर्ड के गठन से कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा।
- राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेश में 100 से अधिक उत्पाद ऐसे हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया जा सकता है। इनमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, फल, सब्जी, हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद, परंपरागत वाद्ययंत्र अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को कानूनीतौर पर संरक्षण मिल जाएगा।
- गौरतलब है कि अब तक प्रदेश के नौ उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इनमें तेजपात, बासमती चावल, ऐपण आर्ट, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, च्यूरा ऑयल तथा टम्टा शामिल हैं।
- इसके अलावा 14 अन्य उत्पादों के जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इनमें बेरीनाग चाय, मंडुवा, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, लखोरी मिर्च, पहाड़ी तुअर दाल, बुरांश जूस, सज़ावटी मोमबत्ती, कुमाऊँनी पिछोड़ा, कंडाली (बिच्छू बूटी) फाइबर शामिल हैं।
- विदित है कि क्षेत्रविशेष के उत्पादों को भौगोलिक संकेत दिया जाता है, जिसका एक विशेष भौगोलिक महत्त्व व स्थान होता है। उसी भौगोलिक मूल के कारण उत्पादविशेष गुण व पहचान रखता है। जीआई टैग मिलने के बाद कोई अन्य उत्पाद की नकल नहीं कर सकता है।

उत्तराखंड के सात ज़िलों में खुलेंगे क्रिटिकल केयर सेंटर

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के सात जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर स्थापित किये जाएंगे। सभी सेंटरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। इन सेंटरों को स्थापित करने के लिये केंद्र सरकार की ओर से बजट दिया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रत्येक सेंटर के निर्माण पर 7 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से 166 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि केंद्र ने एनएचएम के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये उत्तराखंड को सात क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के लिये धनराशि मंज़ूर की है। इन सेंटरों को चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी ज़िलों में बनाया जाएगा।
- ज़िला अस्पतालों के आसपास सेंटर के लिये 1550 वर्गमीटर जगह चयनित कर डीपीआर तैयार की जा रही है। कुमाऊँ मंडल में तीन ज़िलों में ब्रिडकुल और गढ़वाल मंडल के चार ज़िलों में सिंचाई विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य किया जाएगा।
- क्रिटिकल केयर सेंटर बनने के बाद प्रदेश के लोगों को आपात स्थिति में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। इनमें महामारी या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित गंभीर मरीज़ों और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को एक ही जगह पर सभी चिकित्सा सुविधाएँ दी जाएंगी।
- क्रिटिकल केयर सेंटर में सभी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएँ मिलेंगी, जिनमें हृदय रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग समेत अन्य तमाम बीमारियों के इलाज के लिये आधुनिक चिकित्सा उपकरण होंगे। इसके अलावा महामारी से निपटने और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को भी आपात स्थिति में एक ही जगह सभी इलाज की सुविधाएँ मिलेंगी। सेंटर में डायलिसिस, ऑक्सीजन, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड समेत अन्य सभी प्रकार की जाँच की जाएंगी।

उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड के बेहतर संचालन हेतु बनेगा 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट'

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पी.सी. दुमका ने बताया कि कर्मकार बोर्ड के क्रियाकलापों व अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को लागू करने के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) का प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही नए बदलाव लागू हो जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में साइकिल आवंटन जैसे घोटाले रोकने के लिये ऑनलाइन कवच तैयार किया जा रहा है। इसमें जहाँ चार लाख श्रमिकों की सभी योजनाएँ ऑनलाइन होंगी तो उन आवेदनों पर कार्रवाई के लिये अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है।
- बोर्ड के बेहतर संचालन के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) भी बनाई जा रही है। इसमें श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो विभिन्न राज्यों की बेहतर योजनाओं को उत्तराखंड में धरातल पर उतारेंगे। ।
- कर्मकार बोर्ड की सभी योजनाएँ पूरी तरह से ऑनलाइन की जा रही हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे, जो निर्धारित समयावधि में पूरे करने होंगे। साइकिल आवंटन से लेकर सभी योजनाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। फाइलों को ऑनलाइन ग्रीन, येलो, रेड का टैग दिया जाएगा।
- हर अधिकारी को रोजाना सुबह लंबित फाइलों की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस से मिल जाएगी। अगर श्रमिक पंजीकरण को 30 दिन का समय तय किया जाएगा तो 20 दिन तक फाइल ग्रीन दिखेगी, 20 से 30 दिन के बीच येलो और फिर 30 पूरे होते ही रेड हो जाएगी, जिसकी जानकारी आला अधिकारियों तक भी चली जाएगी। काम न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून-अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

26 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 'उड़ान योजना'के तहत देहरादून-अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. रवि शंकर ने कहा कि देहरादून से अल्मोड़ा के लिये हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोग भी कम समय में सफर कर सकेंगे।
- उन्होंने बताया कि अभी डीजीसीए की ओर से हेली सेवा को सप्ताह में एक दिन चलाने की अनुमति दी गई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे प्रतिदिन भी किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से देहरादून से अल्मोड़ा के लिये हेली सेवा संचालित करने की अनुमति देने की मांग की थी।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पवन हंस को देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा संचालित करने की अनुमति दी है।
- इससे डेढ़ घंटे में दून से अल्मोड़ा पहुँच सकेंगे। सड़क मार्ग से 12 से 13 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। हेली सेवा का किराया प्रति यात्री 7700 रुपए तय किया गया है।
- हेली सेवा जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पंतनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ तक चलेगी। यही रूट वापसी का भी रहेगा।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आठ से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करते हुए कई अन्य घोषणाएँ भी कीं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना'से कुल 3900 बालक एवं बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इसके बाद 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में पहले की तरह चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फिर से प्रयास किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक ज़िले में आठ-आठ खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी। मलखंब खेल को नीति में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही खेल विभाग में अनुबंध रखे प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुबंध प्रशिक्षकों के समान मानदेय दिया जाएगा।
- कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति उनकी प्रतिभा पर निर्भर करेगी। खेल छात्रवृत्ति पेंशन योजना नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिये दी जा रही है।

राज्य में 33 नए पर्यटन स्थलों पर बनेंगे हेलीपैड और हेलीपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 33 पर्यटक स्थलों पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाए जाने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में चारधाम के अलावा प्रदेश की खूबसूरती और आबोहवा से पर्यटन क्षेत्र में काफी संभावनाएँ हैं। उन्होंने पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अधिक-से-अधिक हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स बनाए जाने के निर्देश दिये।

नोट :

- उन्होंने कहा कि राज्य में जॉय राइड्स की काफी संभावनाएँ हैं। इसके साथ ही हिमालय दर्शन जैसी योजनाओं को अधिक-से-अधिक स्थानों से संचालित किया जाए।
- मुख्य सचिव ने कहा कि हेलीपोर्ट और हेलीपैड का मास्टर प्लान बनाते समय भविष्य की संभावनाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए योजना बनाई जाए। इन हेलीपोर्ट और हेलीपैड्स का ट्रैफिक प्लान अगले 20, 25, 50 साल के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।
- उन्होंने कहा कि रामनगर में हेलीपैड और हेलीपोर्ट की अधिक संभावनाएँ हैं। उन्होंने डीएम नैनीताल को इस पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार जैसे पर्यटन स्थलों में दो या उससे अधिक हेलीपोर्ट या हेलीपैड बनाने के निर्देश दिये।
- बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 83 हेलीपैड हैं, जिनमें 51 सरकारी और 32 प्राइवेट हैं। 22 हेलीपैड पर काम चल रहा है।

5 जी नेटवर्क के लिये पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि 5जी नेटवर्क को उत्तराखंड में सुगमता से लाने के लिये राइट ऑफ वे पॉलिसी में संशोधन के साथ ही सरकार, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को एडॉप्ट करेगी।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में 5जी नेटवर्क के लिये पॉलिसी बनाने के लिये राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 5जी नेटवर्क के लिये पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में 2018 में नेटवर्क कनेक्टिविटी की राह आसान बनाने, मोबाइल टावर लगाने से लेकर दूरसंचार से जुड़ी गतिविधियों के लिये राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 लागू की गई थी।
- इस पॉलिसी में संशोधन होने के बाद प्रदेश में 5जी नेटवर्क के लिये मोबाइल टावर लगाने से लेकर इसकी लाइन बिछाने तक का पूरा काम आसान हो जाएगा। इसके लिये केंद्र सरकार की नियमावली को एडॉप्ट किया जाएगा।

The Vision

नोट :